(c) what is the present position and by when they are likely to be released; and

(d) what is the present number of Afghan and other foreign militants in Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir Valley and Doda and other areas of Jammu?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (c) The aim and effort of Government has been to try and bring about the safe release of the hostages, through a process of dialogue and persuation and by appealing to the sense of reason and humanity among those responsible for the abduction; and to desist from doing anything that could provide encouragement to further acts of terrorism including abduction. Close liaison and contact has also been maintained with the officials of the Missions of the concerned countries, whose nationals have been abducted. Their officials have also been facilitated to visit Srinagar in keeping with the policy of transparency. Statements have also been issued from time to time by almost all the militant/secessionist outfits in J&K, by the Governments of all the concerned countries and organisations like Amnesty International etc. condemning the incident and demanding release of the hostages. Simultaneously, the Government have avoided any precipitate action which could jeopardise the lives of the hostages. As the foreign tourists are still in the captivity of the abductors it is not possible to indicate as to when they will be released.

(d) It is not possible to give the precise number of foreign nationals/ mercenaries operating in the Valley or in the State. There are a number of militant outfits which have foreign mercenaries in their ranks which mainly include the Harkat-ul-Ansar, Hizb-ul-Mujahideen, Lashkar-e-Toiba, Al-Burq, Tahreek-ul-Mujahideen etc. According to information available 328 foreign militants have been killed and 86 arrested till now in the State.

एड्स का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

466. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जिलावार किस-किस गैर सरकारी संगठन को एड्स का मुकाबला करने के लिए वित्तीयं सहायता मिल रही है;

(ख) उन संगठनों को वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में उनकी उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान एक गैर-सरकारी संस्था "शुरूआत" को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में किसी भी एन०जी०ओ० को अनुदान नहीं दिया गया।

(ग) और (घ) एन जी०ओ० जो कि नुक्कड नाटक करते हैं के कार्य निष्पादन ने स्थानीय प्रचार माध्यम का ध्यान आकर्षित किया है।

Plan for making Indian Air Force more effective

467. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a plan for training and making the Indian Air Force more effective by outdating, updating and modernising its fleet;

(b) if so, the broad features of the plan; and

(c) the steps taken and being taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) Modernisation of the Indian Air Force is an on going process and the underlying theme is to have a 'lean and mean' force. Accordingly, efforts are made to modernise the IAF by induction of combat aircraft and weapon systems with improved technology to replace old assets and by undertaking suitable midlife upgrade to enhance mission effectiveness of existing assets. The IAF also adopts a very strict training pattern to ensured a smooth transition of trainee pilots on to front line squadrons of fighter, transport and helicopter fleets.

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

468. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उनका क्या ब्यौरा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र को वर्षवार कितनी धनराशि दी गई है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) उनका वर्षवार जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र सहित गुजरात राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। गुजरात सरकार ने भी अपरंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के लिए अपनी नीति की घोषणा की है, जिसमें ऐसी विद्युत की व्हीलिंग, बैंकिंग तथा वापस खरीद सुविधाएं सम्मिलित हैं।

गुजरात राज्य में 77 मे०वा० से अधिक क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 16 उपयुक्त स्थलों की पहचान की गई है जो अधिकतर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में हैं। क्षेत्र में 500 कि०वा० क्षमता मिड़ जुड़ी बायोमास गैसफायर आधारित विद्युत परियोजना आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत मैकेनिकल, विद्युत तथा तापीय अनुप्रयोगी के लिए लगभग 1485 कि०वा० क्षमता के बराबर बायोमास गैसीफायरों की स्थापना की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कच्छ की खाड़ी में 900 मे०वा० ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए एक तकनीक-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी प्रस्ताव मांगे गए थे तथा 6 प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्रवार तथा जिलावार कोई धनराशि नहीं दी जाती है। फिर भी पिछले तीन वर्षों के दौरान पवन विद्युत तथा बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं के लिए गुजरात राज्य को निम्नलिखित निर्मुक्तियां की गई है।

रुपये लाखों में

1992-93	1993-94	1994-95
18.00	105.49	13.74

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार वास्तविक या वित्तीय लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

Controversial Post of AIIMS Chairman

469. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the activities of the All India Institute of Medical Sciences have been adversely affected because of the continuance of the former Minister of